

जलवायु कार्टवाई के लिए और अधिक प्रयास

द हिन्दू

पेपर- III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी 21 मई, 2024 को एक मील के पत्थर पर पहुँच गई, जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) ने जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर छोटे द्वीप राज्यों के आयोग (COSIS) द्वारा मांगी गई एक सलाहकार राय (राय) दी, जो जलवायु परिवर्तन शमन पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के पक्षों के विशिष्ट दायित्वों के संबंध में थी। COSIS 2021 में स्थापित छोटे द्वीप राज्यों का एक संघ है। ITLOS सलाहकार राय निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा “जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों” पर तय की जाने वाली सलाहकार कार्यवाही के संदर्भ में अधिक ध्यान आकर्षित करती है।

नये तत्व:

आईटीएलओएस ने सीओएसआईएस के अनुरोध को स्वीकार करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसका उद्देश्य उन राज्यों के दायित्वों की पहचान करना था जो सीओएसआईएस समझौते के पक्षकार नहीं हैं। यह तब है जब अनुरोध मुख्य रूप से उन राज्यों के दायित्वों को छूता है जो अनुरोध को अधिकृत करने वाले समझौते के पक्षकार नहीं हैं। न्यायाधिकरण ने अपनी राय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 194(1) के तहत, षषक्षकारों के पास मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) से समुद्री प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए विशिष्ट दायित्व हैं।”

राय ने इस संदेह को भी दूर कर दिया है कि क्या मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 1(1)(4) के अर्थ के भीतर समुद्री पर्यावरण पर संभावित हानिकारक प्रभाव डालने वाले पदार्थ या ऊर्जा की श्रेणी में आने योग्य है।

प्रदूषक के रूप में कार्बन पर फ्लैट का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अपनाई गई स्थिति को पुष्ट करता है कि सतही महासागर वायुमंडल में उत्सर्जित CO2 का लगभग एक चौथाई हिस्सा तेजी से अवशोषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री जल का क्रमिक अम्लीकरण होता है। अन्य ग्रीनहाउस गैसों (जैसे) का यह प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा, समुद्र ग्लोबल वार्मिंग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी (ऊर्जा) का 90% से अधिक अवशोषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का तापमान बढ़ता है और अंततः समुद्र का स्तर बढ़ता है।

इसके कानूनी महत्व को समझना:

रोकथाम या कोई हानि न पहुंचाने के नियम का सिद्धांत, जो साझा प्राकृतिक संसाधनों (दो या अधिक राज्यों के बीच) के विनियमन के प्रति राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ताकि किसी अन्य राज्य में महत्वपूर्ण प्रकृति के सीमापारीय नुकसान से बचा जा सके, जब इस नियम को जलवायु संकट को विनियमित करने के लिए लागू करने की मांग की जाती है, तो इसकी दो मुख्य सीमाएं होती हैं: इसका द्विपक्षीय ढांचे में निहित होना, और, जलवायु परिवर्तन के लिए दायित्व के उल्लंघन को स्थापित करने में जिम्मेदारी और स्थिति से संबंधित बाधाओं के कारण सिद्धांत को मदद नहीं मिलती है।

जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत (जो द्विपक्षीय हितों की तुलना में सामूहिक हित हैं) का पक्ष लेते हुए यह राय एक नया अध्याय जोड़ती है। आवश्यक उपायों को सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते 2015 में निहित प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों के प्रकाश में तय किया जाना चाहिए, और वैश्विक औसत तापमान लक्ष्य के रूप में 2 डिग्री सेल्सियस के बजाय 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।

राय में आवश्यक उपाय करने से संबंधित दायित्व को उचित परिश्रम दायित्व के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन राय की दृष्टि में इसका मानक कठोर है, क्योंकि इस तरह के उत्सर्जन से समुद्री पर्यावरण को गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान होने का जोखिम बहुत अधिक है। लेकिन अनुच्छेद 194(1) के अंतर्गत मानवजनित जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने

के संदर्भ में पक्षों के दायित्व बहुत सामान्य प्रकृति के हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि न तो सभी प्रदूषण (जीएचजी) की रिहाई को रोका जाना चाहिए और न ही मानवजनित जीएचजी उत्सर्जन को तुरंत या अंततः बंद किया जाना चाहिए।

कुछ समय के लिए जीएचजी उत्सर्जन को कम करके धीरे-धीरे समुद्री प्रदूषण को कम करने वाले उपाय पर्याप्त होंगे। फिर भी, आईटीएलओएस द्वारा एक सामान्य दायित्व की पहचान एक बात को रेखांकित करती है – कि राज्यों के पास जलवायु परिवर्तन को संबंधित करने में असीमित विवेकाधिकार नहीं है। सामान्य दायित्व की पहचान मात्र प्रतीकात्मक मूल्य की होगी और अपर्याप्त है।

पर्यावरण कानून की विशेषज्ञ क्रिस्टीना वोइग्ट कहती हैं कि अधिकांश राज्य पहले से ही जलवायु परिवर्तन शमन पर कुछ कार्रवाई लागू कर रहे हैं, मामले का सार जलवायु परिवर्तन को कम करने के दायित्व का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसकी सामग्री है, विशेष रूप से इस दायित्व के संबंध में लागू आचरण का मानक। इस बिंदु को पुष्ट करने के लिए उदाहरण उर्जेडा फाउंडेशन बनाम नीदरलैंड में नीदरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जहां न्यायालय ने माना कि उचित देखभाल के मानक के आलोक में यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ईसीएचआर) से अनुमानित सामान्य शमन दायित्व का पालन करने के लिए, नीदरलैंड को 2020 तक जीएचजी उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 25% कम करना था (सरकार की 17% की अपर्याप्त मौजूदा प्रतिज्ञा के विपरीत)।

न्यायालय ने इस लक्ष्य को मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुमानों और पेरिस समझौते में 2°C तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे कम लागत वाली विधि पर निर्भर करके पहचाना। राय ठोस रूप से उस पद्धति की पहचान करने में सक्षम नहीं है जिसका उपयोग किसी राज्य की शमन कार्रवाई के अपेक्षित स्तर का आकलन करने के लिए किया जा सकता है – जैसा कि उर्जेडा निर्णय में है। इसके अलावा, राय के अनुसार, उठाए जाने वाले आवश्यक उपाय राज्यों के पास उपलब्ध साधनों और उनकी क्षमताओं के अधीन होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि शमन कार्रवाई के अपेक्षित स्तर को तय करने में समानता के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यदि कोई हो।

यद्यपि सलाहकारी राय में कानूनी बल का अभाव होता है, तथापि यह आधिकारिक न्यायिक घोषणाओं की तरह राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित नहीं करती।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है।
- न्यायाधिकरण में 21 स्वतंत्र सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS):

- It is an independent judicial body established by the United Nations Convention.
- There are 21 independent members in the tribunal.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की भूमिका की चर्चा कीजिए साथ ही चर्चा करें कि जलवायु कार्रवाई के लिए और क्या प्रयास करने की आवश्यकता है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की भूमिका की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में जलवायु कार्रवाई के लिए और प्रयासों की आवश्यकता की चर्चा करें। साथ ही इन प्रयासों का उल्लेख भी करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।